

# एनएचआरसी जांच के बीच 1,000 नेपाली छात्र केआईआईटी विश्वविद्यालय लौटे

वैभव न्युज ■ भुवनेश्वर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और ओडिशा पुलिस द्वारा केआईआईटी परिसर में एक नेपाली छात्रा की कथित आत्महत्या की जांच के बीच, विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि 16 फरवरी को हुए विरोध के बाद परिसर छोड़ने वाले 1,100 में से 1,000 नेपाली छात्र वापस आ गए हैं। निजी विश्वविद्यालय ने छात्रों की वापसी का यह दावा शुक्रवार को तब किया जब इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब दिया। ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय में उचित शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। केआईआईटी ने एक बयान में कहा,

कुल 1,100 में से एक हजार नेपाली छात्र अपने अकादमिक कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए लौट आए हैं, जबकि शेष 100 भी जल्द ही वापस आ जाएंगे। विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि छात्रों की वापसी इस संस्थान और इसके अंतरराष्ट्रीय छात्रों, खासतौर से नेपाल से आए छात्रों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। विश्वविद्यालय के छात्रावास के कमरे में नेपाली छात्रा प्रकृति लाम्साल (20 वर्ष) की 16 फरवरी को कथित आत्महत्या के बाद अन्य नेपाली छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान केआईआईटी कर्मचारियों ने कथित तौर पर नेपाली छात्रों को जबरन परिसर से बाहर किया और अभद्र भाषा का प्रयोग कर उनके साथ मारपीट भी की। इस घटना को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने भी चिंता व्यक्त की थी।

बाद में, विश्वविद्यालय ने माफी मांगते हुए छात्रों से परिसर में लौटने का अनुरोध किया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने परिसर में लौटे नेपाली छात्रों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने छात्रों की वापसी के लिए हेल्पडेस्क बनाया और अंतरराष्ट्रीय छात्र सुविधा प्रकोष्ठ शुरू किया जिससे सभी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों की सहायता हो सके। विश्वविद्यालय ने छात्रों की वापसी के लिए केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय, ओडिशा सरकार, नेपाल सरकार और नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के प्रति आभार व्यक्त किया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समन्वय में केआईआईटी ने सामान्य स्थिति बहाल करने तथा सभी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं।

# एनएचआरसी जांच के बीच एक हजार नेपाली छात्र केआईआईटी विवि लौटे

भुवनेश्वर। (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और ओडिशा पुलिस द्वारा केआईआईटी परिसर में एक नेपाली छात्रा की कथित आत्महत्या की जांच के बीच, विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि 16 फरवरी को हुए विरोध के बाद परिसर छोड़ने वाले 1,100 में से 1000 नेपाली छात्र वापस आ गए हैं। निजी विश्वविद्यालय ने छात्रों की वापसी का यह दावा शुरुवार को तब किया जब इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब दिया। ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय में उचित शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। केआईआईटी ने एक बयान में कहा, 'कुल 1,100 में से एक हजार नेपाली छात्र अपने अकादमिक कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए लौट आए हैं, जबकि शेष 100 भी जल्द ही वापस आ जाएंगे। विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि छात्रों की वापसी इस संस्थान और इसके अंतरराष्ट्रीय छात्रों, खासतौर से नेपाल से आए छात्रों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। विश्वविद्यालय के छात्रावास के कमरे में नेपाली छात्रा प्रकृति लाम्सा (20 वर्ष) की 16 फरवरी को कथित आत्महत्या के बाद अन्य नेपाली छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान केआईआईटी कर्मचारियों ने कथित तौर पर नेपाली छात्रों को जबरन परिसर से बाहर किया और अभद्र भाषा का प्रयोग कर उनके साथ मारपीट भी की। इस घटना को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने भी चिंता व्यक्त की थी। बाद में, विश्वविद्यालय ने माफी

मांगते हुए छात्रों से परिसर में लौटने का अनुरोध किया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने परिसर में लौटे नेपाली छात्रों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने छात्रों की वापसी के लिए हेलपडेस्क बनाया और अंतरराष्ट्रीय छात्र सुविधा प्रकोष्ठ शुरू किया जिससे सभी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों की सहायता हो सके। एक बयान में विश्वविद्यालय ने छात्रों की वापसी के लिए केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय, ओडिशा सरकार, नेपाल सरकार और नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के प्रति आभार व्यक्त किया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समन्वय में केआईआईटी ने सामान्य स्थिति बहाल करने तथा सभी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय ने कहा कि इन प्रयासों से नेपाली छात्रों नए विश्वास के साथ परिसर में वापस लौटे हैं। इसमें कहा गया है, 'विश्वविद्यालय ने अपने सभी छात्रों के लिए समावेशी, सुरक्षित और शैक्षणिक रूप से समृद्ध वातावरण बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। एनएचआरसी के निर्देशानुसार, उनकी टीम छात्रा की मौत और केआईआईटी कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर नेपाली छात्रों को परेशान करने की घटना की जांच कर रही है। आयोग ने टीम को 10 मार्च तक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने को कहा है। ओडिशा पुलिस और एनएचआरसी के अलावा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति भी केआईआईटी की घटना की जांच कर रही है।

**ODISHA**

**1,000 Nepalese  
students have  
returned: KIIT**

*Bhubaneswar:* Amid the probe by the NHRC and Odisha Police into the alleged suicidal death of a B Tech girl student, KIIT University has claimed that 1,000 of the 1,100 Nepalese students who left the campus in the wake of the February 16 unrest have returned to the institute in Bhubaneswar. The institute tendered an apology and urged the students to return to campus. **PTI**



KIIT girl student death

# NHRC team also visits KISS for probe

Report to be  
submitted by  
March 10

PNS ■ BHUBANESWAR

The National Human Rights Commission (NHRC) team probing the death of Nepalese student Prakriti Lamsal at KIIT University in Bhubaneswar visited the Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) here on Saturday

as part of a broader investigation into various allegations.

The NHRC has directed the probe team to submit the investigation report by March 10.

On Thursday, the NHRC had requested the institution's students as well as the general public to come forward with any information that they might have to help in the investigation.

Subsequently, an RTI activ-

ist had brought allegations including the poor welfare of students at the KISS, land encroachment by the institution.

Taking possible note of it, the NHRC team visited the KISS campus on the day and took stock of the situation. But the team members did not reveal the exact nature and angles probed.

"We recorded statements of multiple people at KIIT University as per the orders of the

NHRC. We have interrogated as many people as we deemed fit for the case. Today marked the third and final day of our probe and details of it will be released by the council," said NHRC Law Registrar Joginder Singh.

For three consecutive days, the NHRC's independent team conducted an on-site investigation into the incident, recording statements from KIIT authorities and students.

# 1,000 students from Nepal returned amid NHRC probe: KIIT

**Press Trust of India**  
BHUBANESWAR

Amid the probe by the National Human Rights Commission (NHRC) and Odisha Police into the alleged suicidal death of a B. Tech girl student, KIIT University has claimed that 1,000 of the 1,100 Nepalese students who left the campus in the wake of the February 16 unrest have returned to the institute.

The private university made this claim on Friday after Higher Education Minister Suryabanshi Suraj informed the Assembly that the government has formed a professors' committee to ensure a proper academic environment on the KIIT campus.

"As many as 1,000 Nepalese students have returned...The remaining 100 students will be arriving soon," the KIIT said in a statement.

The Nepalese students were allegedly evicted from the campus by KIIT employees after they demanded justice for 20-year-old Prakriti Lamsal, who died by suicide in her hostel room on February 16. The students were allegedly beaten up, verbally

**Govt. has set up a help desk for their return, started a cell for international students**

abused and even thrown out of the campus as they staged a demonstration over the death.

Nepal Prime Minister K.P. Sharma Oli had expressed concern over the manner in which the Nepalese students were treated by the KIIT authorities. Later, the institute tendered an apology and urged the students to return to campus.

The government has, meanwhile, set up a help desk to facilitate the return of Nepalese students and also launched a dedicated International Student Facilitation Cell to support and assist international students across universities in the State.

The NHRC team has been undertaking an "on-spot" inquiry into the death of the student and subsequent harassment of the Nepalese students allegedly by KIIT employees.

The Commission has asked the team to submit its findings by March 10.

# 1,000 Nepalese students return to KIIT campus amid NHRC probe

BHUBANESWAR, Mar 8 (PTI)

AMID the probe by the NHRC and Odisha Police into the alleged suicidal death of a B Tech girl student, KIIT University has claimed that 1,000 of the 1,100 Nepalese students who left the campus in the wake of the February 16 unrest have returned to the institute in Bhubaneswar.

The private university made this claim on Friday after Odisha's Higher Education Minister, Suryabanshi Suraj, informed the Assembly that the state government formed a Professors'

Committee to ensure a proper academic environment on the KIIT campus.

"As many as 1,000 Nepalese students out of 1,100 have returned to KIIT-DU to resume their academic pursuits after temporarily leaving the campus in the wake of the February 16 incident. The remaining 100 students are on their way and will be arriving soon," the KIIT said in a statement, adding that the students' return demonstrates the strong ties between the institute and its international student community, particularly

from Nepal. The Nepalese students were allegedly evicted from the campus by KIIT employees after they demanded justice for 20-year-old Prakriti Lamsal, who died by suicide in her hostel room on February 16.

The students allegedly were beaten up, verbally abused and even thrown out of the campus as they staged a demonstration over the Nepalese girl student's death. Nepal Prime Minister K P Sharma Oli had expressed concern over the manner in which the Nepalese students were treated by the KIIT authorities.



# एनएचआरसी जांच के बीच एक हजार नेपाली छात्र केआईआईटी विवि लौटे

**भुवनेश्वर।** (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और ओडिशा पुलिस द्वारा केआईआईटी परिसर में एक नेपाली छात्रा की कथित आत्महत्या की जांच के बीच, विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि 16 फरवरी को हुए विरोध के बाद परिसर छोड़ने वाले 1,100 में से 1000 नेपाली छात्र वापस आ गए हैं। निजी विश्वविद्यालय ने छात्रों की वापसी का यह दावा शुक्रवार को तब किया जब इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब दिया। ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय में उचित शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। केआईआईटी ने एक बयान में कहा, 'कुल 1,100 में से एक हजार नेपाली छात्र अपने अकादमिक कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए लौट आए हैं, जबकि शेष 100 भी जल्द ही वापस आ जाएंगे।' विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि छात्रों की वापसी इस संस्थान और इसके अंतरराष्ट्रीय छात्रों, खासतौर से नेपाल से आए छात्रों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। विश्वविद्यालय के छात्रावास के कमरे में नेपाली छात्रा प्रकृति लाम्सा (20 वर्ष) की 16 फरवरी को कथित आत्महत्या के बाद अन्य नेपाली छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान केआईआईटी कर्मचारियों ने कथित तौर पर नेपाली छात्रों को जबरन परिसर से बाहर किया और अभद्र भाषा का प्रयोग कर उनके साथ मारपीट भी की। इस घटना को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने भी चिंता व्यक्त की थी। बाद में, विश्वविद्यालय ने माफी

मांगते हुए छात्रों से परिसर में लौटने का अनुरोध किया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने परिसर में लौटे नेपाली छात्रों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने छात्रों की वापसी के लिए हेलपडेस्क बनाया और अंतरराष्ट्रीय छात्र सुविधा प्रकोष्ठ शुरू किया जिससे सभी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों की सहायता हो सके। एक बयान में विश्वविद्यालय ने छात्रों की वापसी के लिए केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय, ओडिशा सरकार, नेपाल सरकार और नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के प्रति आभार व्यक्त किया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समन्वय में केआईआईटी ने सामान्य स्थिति बहाल करने तथा सभी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय ने कहा कि इन प्रयासों से नेपाली छात्रों ने विश्वास के साथ परिसर में वापस लौटे हैं। इसमें कहा गया है, 'विश्वविद्यालय ने अपने सभी छात्रों के लिए समावेशी, सुरक्षित और शैक्षणिक रूप से समृद्ध वातावरण बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि की है।' एनएचआरसी के निर्देशानुसार, उनकी टीम छात्रा की मौत और केआईआईटी कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर नेपाली छात्रों को परेशान करने की घटना की जांच कर रही है। आयोग ने टीम को 10 मार्च तक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने को कहा है। ओडिशा पुलिस और एनएचआरसी के अलावा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति भी केआईआईटी की घटना की जांच कर रही है।

## एचएचआरसी ने 100 दिन में 1,091 केस निपटाए

रोड़ीग्रद | हरियाणा मानवाधिकार  
आयोग (एचएचआरसी) ने अपने  
पहले 100 दिनों में मामले निपटान  
में उपलब्धि हासिल की है। अध्यक्ष  
न्यायमूर्ति ललित बत्रा, सदस्य कुलदीप  
जैन व दीप भाटिया के नेतृत्व में त्वरित  
कार्रवाई की गई। जनसंपर्क अधिकारी  
छै. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि इस  
अवधि में 1,091 केस हल किए गए।



## एचएचआरसी ने 100 दिन में 1,091 केस निपटाए

चंडीगढ़ | हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने अपने पहले 100 दिनों में मामले निपटान में उपलब्धि हासिल की है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा, माननीय सदस्य कुलदीप जैन व दीप भाटिया के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई की गई। प्रोटोकॉल-कम-जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि इस अवधि में 1,091 केस हल किए। जिसमें 5

स्व-प्रेरित मामले व 56 ऐसे मामले शामिल थे जो दो साल से अधिक समय से लंबित थे। इस दौरान विभिन्न जिलों में कुल 815 नए मामले दर्ज किए। सबसे अधिक केस फरीदाबाद, गुरुग्राम में (94-94 केस) दर्ज हुए। हिसार में 54, करनाल में 41 व महेंद्रगढ़ में 42 केस रहे। वहीं, सबसे कम मामले चरखी दादरी (6), फतेहबाद (13) और जींद में (16) दर्ज किए गए।



NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

# दैनिक सवेरा

आँदरे ले उजारे की ओर...

टाइम्स

## 100 दिन, 1100 मामले : हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने दिलाया त्वरित न्याय

### न्याय की दिशा में कदम: मानवाधिकारों की रक्षा और ऐतिहासिक मामले निपटान

**सवेरा ब्यूरो**

चंडीगढ़, 3 मार्च : हरियाणा मानवाधिकार आयोग, जिसे 27 नवंबर 2024 को पुनर्गठित किया गया था, ने अपने पहले 100 दिनों का सफलतापूर्वक संचालन पूरा कर लिया है, जो मामलों के निपटान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा और माननीय सदस्य कुलदीप जैन एवं दीप भाटिया के नेतृत्व में, आयोग ने राज्य भर में मानवाधिकार मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की है। डा. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि आयोग हरियाणा में न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रतिबद्ध



है। इस अविध के दौरान कुल 1,091 मामलों का निपटान किया गया, जिसमें पांच स्व-प्रेरित मामले और 56 ऐसे मामले शामिल थे जो दो साल से अधिक समय से लंबित थे। एचएचआरसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मासिक मामलों के आंकड़े निम्नानुसार हैं।

पहले 100 दिनों में हरियाणा में 815 नए मामले दर्ज : हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने अपने पहले 100 दिनों के संचालन के दौरान हरियाणा के विभिन्न जिलों में कुल 815 नए मामले दर्ज किए। माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा और माननीय सदस्य कुलदीप जैन एवं दीप भाटिया के नेतृत्व में, आयोग ने पूरे राज्य में मानवाधिकार उल्लंघनों को

#### एचएचआरसी की महत्वपूर्ण पहल: मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में प्रभावशाली कदम

माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा, माननीय सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया ने भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तत्वाधान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान आयोग ने अन्य मानवाधिकार आयोगों के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और न्याय व मानवाधिकारों की वकालत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

#### जेलों का निरीक्षण और सुविधाजनक शिकायत प्रक्रिया

आयोग के अध्यक्ष तथा दोनों सदस्यों ने अंबाला और कुरु क्षेत्र की जेलों का दौरा किया ताकि वहां मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा की जा सके और कैदियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के प्रोटेक्टॉल-कम-जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि आयोग पूरे राज्य में मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के अपने मिशन पर दृढ़ता से काम कर रहा है। अब हरियाणा के नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए चंडीगढ़ या गुरु ग्राम जाने की आवश्यकता नहीं है। वे ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क है। इसके अतिरिक्त, तेजी से सुनवाई और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए एचएचआरसी ने गुरु ग्राम में एक कैंप कोर्ट की स्थापना की है, जो हर महीने दो बार बैठता है और दक्षिणी हरियाणा के छह जिलों के मामलों की सुनवाई करता है।

#### एचएचआरसी ने पहले 100 दिनों में 13 श्रेणियों में दर्ज किए 815 मामले

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने अपने पहले 100 दिनों के भीतर 13 विभिन्न श्रेणियों में कुल 815 मामले दर्ज किए, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में न्याय को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सका। एचएचआरसी की

नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक मामले पुलिस से संबंधित थे (310 मामले), इसके बाद विविध श्रेणी (291 मामले) और सेवा से जुड़े मामले (60 मामले) दर्ज किए गए। अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियों

में शामिल हैं: महिलाओं से संबंधित मामले-44, स्वास्थ्य से जुड़े मामले-23, बाल अधिकार से जुड़े मामले-14, जेल से संबंधित मामले-24, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग से जुड़े 8 मामले हैं।

सक्रिय रूप से संबोधित किया है। सबसे अधिक मामले फरीदबाद और गुरु ग्राम (94-94 मामले) में दर्ज किए। इसके बाद हिसार (54), करनाल (41) और महेंद्रगढ़ (42) का स्थान रहा। वहीं, सबसे कम मामले चरखी दादरी (6), फतेहाबाद (13) और जींद (16) में दर्ज किए गए।

PIB

## **NHRC, India's second ITEC Executive capacity-building programme on human rights for NHRIs of Global South concludes**

The programme organised in partnership with the Ministry of External Affairs, Government of India

In his valedictory address, NHRC, India Chairperson, Justice Shri V. Ramasubramanian emphasised free exchange of knowledge as the foundation of a better world

Says, humanity has the power to create a just and harmonious society on Earth

35 senior functionaries from 11 NHRIs of Global South addressed by the several eminent speakers on various aspects of governance and human rights

<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2109515>

Posted On: 08 MAR 2025 7:56PM by PIB Delhi

The 2nd six-day ITEC Executive Capacity Building Programme on Human Rights for senior functionaries of the National Human Rights Institutions (NHRIs) of Global South organised by the National Human Rights Commission (NHRC), India in partnership with the Ministry of External Affairs, successfully concluded. The valedictory session was addressed by the NHRC, India Chairperson, Justice Shri V. Ramasubramanian in the presence of Members Justice (Dr.) Bidyut Ranjan Sarangi, Smt. Vijaya Bharathi Sayani & Secretary General, Shri Bharat Lal.

The programme, which began on Monday 3rd March, 2025, witnessed participation of 35 senior functionaries from 11 NHRIs of Madagascar, Uganda, Timor Leste, DR Congo, Togo, Mali, Nigeria, Egypt, Tanzania, Burundi and Turkmenistan. The programme included interactive sessions with eminent persons and domain experts, and participants got exposure to various aspects of civic and political rights as well as socio-economic and cultural rights enjoyed by the people of India. During the 6-day programme, speakers included NHRC Chairperson, Members, Secretary General Shri V. K. Paul, Member, NITI Aayog & Shri Rajeev Kumar, Former Chief Election Commissioner of India, Shri Yugal Kishore Joshi, Mission Director at NITI Aayog & Ambassador Asoke Kumar Mukerji, former PR of India to UN, Mr Chris Garroway, Economist & Development Coordinator, United Nations, Shri Manoj Yadava, former DG(I), Shri Surajit Dey, former Registrar (Law) and Smt Anita Sinha and Shri D. K. Nim , former Joint Secretaries of the NHRC. The programme was also enriched by the sharing of the experiences by the participating senior functionaries of various NHRIs.

In his closing remarks, the NHRC Chairperson, Justice Shri V. Ramasubramanian, expressed his heartfelt gratitude to all attendees. He emphasised that free exchange of knowledge are the foundation of a better world, stating that humanity has the power to create a just and harmonious society on Earth. Citing the Rig Veda, he underscored the



importance of welcoming noble thoughts from all directions and reiterated that the ultimate aim of all human endeavors is to enhance the quality of life for all.

He eloquently reflected on the universal essence of humanity, drawing parallels between the unity of mankind and the singularity of gold despite the multitude of jewels it forms. Concluding his address, he reminded all participants that the highest virtue is to be a good human being. Reiterating his remarks in the inaugural session, the NHRC, India Chairperson said that platforms like ITEC provide an opportunity to share and exchange each other's rich cultural diversity and human rights values, to think and find ways on how best to address the ever-emerging human rights challenges.

NHRC, India Member, Justice (Dr.) Bidyut Ranjan Sarangi, acknowledged the participants' dedication to human rights advocacy and applauded their enthusiasm and commitment to meaningful change. He reaffirmed the NHRC India's commitment to strengthen future collaborations with NHRIs worldwide. Quoting the philosophy of "Vasudhaiva Kutumbakam" (The World is One Family), he emphasised NHRC's vision of fostering global solidarity in protecting and promoting human rights.

NHRC, India Member, Smt. Vijaya Bharathi Sayani, expressed gratitude to all participants for their valuable contributions, recognising their engagement and willingness to share insights. She emphasised the Commission's commitment to continuous learning and collaboration and extended warm wishes for International Women's Day, underlining the importance of gender equality and human rights for all.

Before this, NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal commended all attendees for their active participation. He highlighted the significance of cooperation among the countries of Global South, emphasising their shared values and mutual learning opportunities. He also discussed the signing of potential Memorandums of Understanding (MoUs) with interested countries to deepen this collaboration. Notably, he offered the NHRC's knowledge and experience in strengthening human rights in their countries including advanced complaint redressal system software, for robust grievance redressal mechanisms and further strengthening human rights enforcement.

The participants also got the opportunity to visit iconic places like Pradhan mantri Museum, Humayun tomb, Taj Mahal, Delhi Haat, etc. to have an exposure to India's rich cultural heritage.

NHRC, India Director, Lt Col Virender Singh, the course coordinator applauded the active engagement of participants and the invaluable exchange of knowledge throughout the programme. Shri Vikram Harimohan Meena, SSP, co-course coordinator emphasised the role of law enforcement in human rights protection, advocating greater synergy between policing and human rights organisations.

\*\*\*\*\*

ANI News

## **NHRC, India's second ITEC Executive capacity-building programme on human rights for NHRIs of Global South concludes**

<https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-indias-second-itec-executive-capacity-building-programme-on-human-rights-for-nhris-of-global-south-concludes20250308223552/>

ANI | Updated: Mar 08, 2025 22:35 IST

New Delhi [India], March 8 (ANI): The ITEC Executive Capacity Building Programme on Human Rights, organised by the National Human Rights Commission (NHRC) in partnership with the Ministry of External Affairs for senior functionaries of the National Human Rights Institutions (NHRIs) of the Global South, concluded on Saturday, the NHRC said in a release. NHRC, India Chairperson Justice V. Ramasubramanian, addressed the valedictory session in the presence of Members Justice Bidyut Ranjan Sarangi, Vijaya Bharathi Sayani, and Secretary General Bharat Lal. The programme, which began on March 3, saw the participation of 35 senior functionaries from 11 NHRIs of Madagascar, Uganda, Timor-Leste, DR Congo, Togo, Mali, Nigeria, Egypt, Tanzania, Burundi, and Turkmenistan. It also included interactive sessions with eminent persons and domain experts, and participants were exposed to various aspects of civic and political rights, as well as socio-economic and cultural rights enjoyed by the people of India.

During the 6-day programme, speakers included NHRC Chairperson, Members, Secretary General V K Paul, NITI Aayog member, Rajeev Kumar, Former Chief Election Commissioner of India, Yugal Kishore Joshi, Mission Director at NITI Aayog, and Ambassador Asoke Kumar Mukerji, former PR of India to UN, Chris Garroway, Economist and Development Coordinator, United Nations, Manoj Yadava, former DG(I), Surajit Dey, former Registrar (Law) and Anita Sinha and D K Nim, former Joint Secretaries of the NHRC, according to a statement from the NHRC. The NHRC statement read that the programme was also enriched by the sharing of experiences by the participating senior functionaries of various NHRIs.

In his closing remarks, the NHRC Chairperson, Justice V Ramasubramanian, expressed his heartfelt gratitude to all attendees. He emphasised that free exchange of knowledge is the foundation of a better world, stating that humanity has the power to create a just and harmonious society on Earth. Citing the Rig Veda, he underscored the importance of welcoming noble thoughts from all directions and reiterated that the ultimate aim of all human endeavors is to enhance the quality of life for all. He reflected on the universal essence of humanity, drawing parallels between the unity of mankind and the singularity of gold despite the multitude of jewels it forms. Concluding his address, he reminded all participants that the highest virtue is to be a good human being.

Reiterating his remarks in the inaugural session, the NHRC, India Chairperson said that platforms like ITEC provide an opportunity to share and exchange each other's rich cultural diversity and human rights values, to think and find ways on how best to address the ever-emerging human rights challenges. NHRC, India Member, Justice (Dr) Bidyut Ranjan Sarangi, acknowledged the participants' dedication to human rights advocacy and applauded their enthusiasm and commitment to meaningful change. He reaffirmed the NHRC India's commitment to strengthening future collaborations with NHRIs worldwide. Quoting the philosophy of "Vasudhaiva Kutumbakam" (The World is One Family), he emphasised NHRC's vision of fostering global solidarity in protecting and promoting human rights. NHRC India Member, Vijaya Bharathi Sayani, expressed gratitude to all participants for their valuable contributions, recognising their engagement and willingness to share insights. She emphasised the Commission's commitment to continuous learning and collaboration and extended warm wishes for International Women's Day, underlining the importance of gender equality and human rights for all. Before this, NHRC India Secretary General Bharat Lal commended all attendees for their active participation. He highlighted the significance of cooperation among the countries of the Global South, emphasising their shared values and mutual learning opportunities. He also discussed the signing of potential Memorandums of Understanding (MoUs) with interested countries to deepen this collaboration. Notably, he offered the NHRC's knowledge and experience in strengthening human rights in their countries, including advanced complaint redressal system software, for robust grievance redressal mechanisms and further strengthening human rights enforcement. The participants also got the opportunity to visit iconic places like Pradhan Mantri Museum, Humayun Tomb, Taj Mahal, Delhi Haat, etc., to have an exposure to India's rich cultural heritage.

NHRC India Director Lt Col Virender Singh, the course coordinator, applauded the active engagement of participants and the invaluable exchange of knowledge throughout the programme. Vikram Harimohan Meena, SSP, co-course coordinator, emphasised the role of law enforcement in human rights protection, advocating greater synergy between policing and human rights organisations. (ANI)



Janta Se Rishta

## **NHRC, वैश्विक दक्षिण के NHRs के लिए मानवाधिकारों पर भारत का दूसरा ITEC कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम**

<https://jantaserishta.com/delhi-ncr/nhrc-indias-2nd-itec-executive-capacity-building-programme-on-human-rights-for-nhris-of-global-south-3879497>

Gulabi Jagat | 8 Mar 2025 11:08 PM

New Delhi: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए आयोजित मानवाधिकारों पर आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ, एनएचआरसी ने एक विज्ञप्ति में कहा। एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम ने सदस्य न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारंगी, विजया भारती सयानी और महासचिव भरत लाल की उपस्थिति में समापन सत्र को संबोधित किया। 3 मार्च को शुरू हुए इस कार्यक्रम में मेडागास्कर, युगांडा, तिमोर-लेस्ते, डीआर कांगो, टोगो, माली, नाइजीरिया, मिस्र, तंजानिया, बुरुंडी और तुर्कमेनिस्तान के 11 एनएचआरआई के 35 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। एनएचआरसी के एक बयान के अनुसार, 6 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं में एनएचआरसी अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव वीके पॉल, नीति आयोग के सदस्य, राजीव कुमार, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, युगल किशोर जोशी, नीति आयोग में मिशन निदेशक, और राजदूत अशोक कुमार मुखर्जी, भारत के पूर्व पीआर संयुक्त राष्ट्र, क्रिस गैरोवे, अर्थशास्त्री और विकास समन्वयक, संयुक्त राष्ट्र, मनोज यादव, पूर्व महानिदेशक (आई), सुरजीत डे, पूर्व रजिस्ट्रार (कानून) और अनीता सिन्हा और डीके निम, एनएचआरसी के पूर्व संयुक्त सचिव शामिल थे। एनएचआरसी के बयान में कहा गया है कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न एनएचआरआई के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा अनुभवों को साझा करने से भी कार्यक्रम समृद्ध हुआ।

अपने समापन भाषण में एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने सभी उपस्थित लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान का मुक्त आदान-प्रदान एक बेहतर दुनिया की नींव है, उन्होंने कहा कि मानवता में पृथ्वी पर एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की शक्ति है। ऋग्वेद का हवाला देते हुए उन्होंने सभी दिशाओं से महान विचारों का स्वागत करने के महत्व को रेखांकित किया और दोहराया कि सभी मानवीय प्रयासों का अंतिम उद्देश्य सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

उन्होंने मानवता के सार्वभौमिक सार पर विचार किया, मानव जाति की एकता और रत्नों की बहुलता के बावजूद सोने की विलक्षणता के बीच समानताएं खींचीं। अपने संबोधन का समापन करते हुए उन्होंने सभी प्रतिभागियों को याद दिलाया कि सबसे बड़ा गुण एक अच्छा इंसान बनना है। उद्घाटन सत्र में अपनी टिप्पणियों को दोहराते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष ने कहा कि आईटीईसी जैसे मंच एक-दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और मानवाधिकार मूल्यों को साझा करने और आदान-प्रदान करने, लगातार उभरती मानवाधिकार चुनौतियों से निपटने के सर्वोत्तम तरीकों पर विचार करने और खोजने का अवसर प्रदान करते हैं।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी ने मानवाधिकार वकालत के प्रति प्रतिभागियों के समर्पण को स्वीकार किया और सार्थक बदलाव के प्रति उनके उत्साह और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने दुनिया भर के एनएचआरआई के साथ भविष्य के सहयोग को मजबूत करने के लिए एनएचआरसी इंडिया की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। "वसुधैव कुटुम्बकम्" (विश्व एक परिवार है) के दर्शन का हवाला देते हुए, उन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन में वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने के एनएचआरसी के दृष्टिकोण पर जोर दिया।

एनएचआरसी इंडिया की सदस्य विजया भारती सयानी ने सभी प्रतिभागियों के बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त किया, उनकी भागीदारी और अंतर्दृष्टि साझा करने की इच्छा को मान्यता दी। उन्होंने निरंतर सीखने और सहयोग के लिए आयोग की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और सभी के लिए लैंगिक समानता और मानवाधिकारों के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। इससे पहले, एनएचआरसी इंडिया के महासचिव भरत लाल ने सभी उपस्थित लोगों की सक्रिय भागीदारी के लिए सराहना की। उन्होंने वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला, उनके साझा मूल्यों और आपसी सीखने के अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने इस सहयोग को और गहरा करने के लिए इच्छुक देशों के साथ संभावित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने पर भी चर्चा की। उल्लेखनीय रूप से, उन्होंने अपने देशों में मानवाधिकारों को मजबूत करने में एनएचआरसी के ज्ञान और अनुभव की पेशकश की, जिसमें मजबूत शिकायत निवारण तंत्र और मानवाधिकार प्रवर्तन को और मजबूत बनाने के लिए उन्नत शिकायत निवारण प्रणाली सॉफ्टवेयर शामिल है। प्रतिभागियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, दिल्ली हाट आदि जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर जाने का अवसर भी मिला।

एनएचआरसी इंडिया के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह, जो कि पाठ्यक्रम समन्वयक हैं, ने प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी और पूरे कार्यक्रम के दौरान ज्ञान के अमूल्य आदान-प्रदान की सराहना की। सह-पाठ्यक्रम समन्वयक, एसएसपी विक्रम हरिमोहन मीना ने मानवाधिकार संरक्षण में कानून प्रवर्तन की भूमिका पर जोर दिया, तथा पुलिस और मानवाधिकार संगठनों के बीच अधिक तालमेल की वकालत की। (एनआई)

## Business Standard

### **1,000 students from Nepal returned to campus amid NHRC probe: KIIT**

The Nepalese students were allegedly evicted from the campus by KIIT employees after they demanded justice for 20-year-old Prakriti Lamsal, who died by suicide in her hostel room on February 16

[https://www.business-standard.com/india-news/1-000-students-from-nepal-returned-to-campus-amid-nhrc-probe-kiit-125030800329\\_1.html](https://www.business-standard.com/india-news/1-000-students-from-nepal-returned-to-campus-amid-nhrc-probe-kiit-125030800329_1.html)

Press Trust of India Bhubaneswar | 3 min read Last Updated : Mar 08 2025 | 3:04 PM IST

Amid the probe by the NHRC and Odisha Police into the alleged suicidal death of a B Tech girl student, KIIT University has claimed that 1,000 of the 1,100 Nepalese students who left the campus in the wake of the February 16 unrest have returned to the institute in Bhubaneswar.

The private university made this claim on Friday after Odisha's Higher Education Minister, Suryabanshi Suraj, informed the Assembly that the state government formed a professor committee to ensure a proper academic environment on the KIIT campus.

"As many as 1,000 Nepalese students out of 1,100 have returned to KIIT-DU to resume their academic pursuits after temporarily leaving the campus in the wake of the February 16 incident. The remaining 100 students are on their way and will be arriving soon," the KIIT said in a statement, adding that the students' return demonstrates the strong ties between the institute and its international student community, particularly from Nepal.

The Nepalese students were allegedly evicted from the campus by KIIT employees after they demanded justice for 20-year-old Prakriti Lamsal, who died by suicide in her hostel room on February 16.

The students allegedly were beaten up, verbally abused and even thrown out of the campus as they staged a demonstration over the Nepalese girl student's death.

Nepal Prime Minister K P Sharma Oli had expressed concern over the manner in which the Nepalese students were treated by the KIIT authorities.

Later, the institute tendered an apology and urged the students to return to campus.

Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi also assured the complete safety of the Nepalese students after they returned to the campus in KIIT.

The state government has, meanwhile, set up a helpdesk to facilitate the return of Nepalese students and also launched a dedicated International Student Facilitation Cell to support and assist international students across (Public/Private/Deemed) universities in the state.



In a statement, the varsity expressed gratitude to the central government, the Ministry of External Affairs, the Odisha Government, the Nepalese Government, and the Nepalese Embassy in New Delhi for the return of the students.

The authorities also said that in coordination with law enforcement authorities, KIIT had taken immediate steps to restore normalcy and ensure the safety and well-being of all students.

"With the situation stabilized, KIIT-DU engaged in continuous dialogue with the Nepal Embassy, student representatives, and parents to reassure them about the security and support available at the university. Special grievance redressal mechanisms were put in place to address any concerns and enhance the overall student experience," the statement said.

The varsity said that these efforts saw the return of Nepalese students to the campus with renewed confidence".

"The university has reaffirmed its commitment to maintaining an inclusive, safe, and academically enriching environment for all its students," it added.

As directed by the NHRC, its team has been undertaking an on-spot inquiry into the death of the female student and subsequent harassment of the Nepalese students allegedly by KIIT employees.

The NHRC inquiry team, led by its Registrar (Law) Joginder Singh, has collected evidence from the Odisha Police and interacted with the KIIT authorities, students and other persons concerned linked to the incident.

The commission has asked the team to submit its findings by March 10.

Besides Odisha Police and NHRC, the state government's high-level committee headed by the additional chief secretary of the Home Department is also probing the KIIT incident.

The police have meanwhile arrested 11 people, including one engineering student, on the charge of abetment to suicide.

(Only the headline and picture of this report may have been reworked by the Business Standard staff; the rest of the content is auto-generated from a syndicated feed.)

Pioneer

## **1,000 Nepalese students returned to campus amid NHRC probe: KIIT**

<https://www.dailypioneer.com/2025/top-stories/1-000-nepalese-students-returned-to-campus-amid-nhrc-probe--kiit.html>

Saturday, 08 March 2025 | PTI | Bhubaneswar

Amid the probe by the NHRC and Odisha Police into the alleged suicidal death of a B Tech girl student, KIIT University has claimed that 1,000 of the 1,100 Nepalese students who left the campus in the wake of the February 16 unrest have returned to the institute in Bhubaneswar.

The private university made this claim on Friday after Odisha's Higher Education Minister, Suryabanshi Suraj, informed the Assembly that the state government formed a professor committee to ensure a proper academic environment on the KIIT campus.

"As many as 1,000 Nepalese students out of 1,100 have returned to KIIT-DU to resume their academic pursuits after temporarily leaving the campus in the wake of the February 16 incident. The remaining 100 students are on their way and will be arriving soon," the KIIT said in a statement, adding that the students' return demonstrates the strong ties between the institute and its international student community, particularly from Nepal.

The Nepalese students were allegedly evicted from the campus by KIIT employees after they demanded justice for 20-year-old Prakriti Lamsal, who died by suicide in her hostel room on February 16.

The students allegedly were beaten up, verbally abused and even thrown out of the campus as they staged a demonstration over the Nepalese girl student's death.

Nepal Prime Minister K P Sharma Oli had expressed concern over the manner in which the Nepalese students were treated by the KIIT authorities.

Later, the institute tendered an apology and urged the students to return to campus.

Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi also assured the complete safety of the Nepalese students after they returned to the campus in KIIT.

The state government has, meanwhile, set up a helpdesk to facilitate the return of Nepalese students and also launched a dedicated International Student Facilitation Cell to support and assist international students across (Public/Private/Deemed) universities in the state.

In a statement, the varsity expressed gratitude to the central government, the Ministry of External Affairs, the Odisha Government, the Nepalese Government, and the Nepalese Embassy in New Delhi for the return of the students.

The authorities also said that in coordination with law enforcement authorities, KIIT had taken immediate steps to restore normalcy and ensure the safety and well-being of all students.

"With the situation stabilized, KIIT-DU engaged in continuous dialogue with the Nepal Embassy, student representatives, and parents to reassure them about the security and support available at the university. Special grievance redressal mechanisms were put in place to address any concerns and enhance the overall student experience," the statement said.

The varsity said that these efforts saw the return of Nepalese students to the campus with "renewed confidence".

"The university has reaffirmed its commitment to maintaining an inclusive, safe, and academically enriching environment for all its students," it added.

As directed by the NHRC, its team has been undertaking an "on-spot" inquiry into the death of the female student and subsequent harassment of the Nepalese students allegedly by KIIT employees.

The NHRC inquiry team, led by its Registrar (Law) Joginder Singh, has collected evidence from the Odisha Police and interacted with the KIIT authorities, students and other persons concerned linked to the incident.

The commission has asked the team to submit its findings by March 10.

Besides Odisha Police and NHRC, the state government's high-level committee headed by the additional chief secretary of the Home Department is also probing the KIIT incident.

The police have meanwhile arrested 11 people, including one engineering student, on the charge of abetment to suicide.

India Today

## **1,000 Nepalese students return to KIIT as rights panel probes student's death**

Nepalese students were allegedly evicted from the campus by KIIT employees after they demanded justice for the 20-year-old, who died by suicide in her hostel room on February 16.

<https://www.indiatoday.in/amp/india/odisha/story/1000-nepalese-students-return-kiit-national-human-rights-commission-probes-student-death-2690834-2025-03-08>

Press Trust of India | Bhubaneswar, UPDATED: Mar 8, 2025 15:09 IST

Posted By: Karishma Saurabh Kalita

Subscribe to Notifications

In Short

Odisha's Higher Education Minister announces set up of professor committee

KIIT apologises, assures safety after eviction and abuse allegations

11 arrests made so far, amultiple committees probing student's death

Amid the probe by the NHRC and Odisha Police into the alleged suicide of a BTech student, KIIT University has claimed that 1,000 of the 1,100 Nepalese students who left the campus in the wake of the February 16 unrest have returned to the institute in Bhubaneswar.

The private university made this claim on Friday after Odisha's Higher Education Minister, Suryabanshi Suraj, informed the Assembly that the state government formed a professor committee to ensure a proper academic environment on the KIIT campus.

"As many as 1,000 Nepalese students out of 1,100 have returned to KIIT-DU to resume their academic pursuits after temporarily leaving the campus in the wake of the February 16 incident. The remaining 100 students are on their way and will be arriving soon," the KIIT said in a statement, adding that the students' return demonstrates the strong ties between the institute and its international student community, particularly from Nepal.

The Nepalese students were allegedly evicted from the campus by KIIT employees after they demanded justice for the 20-year-old, who died by suicide in her hostel room on February 16.

The students were allegedly beaten up, verbally abused and even thrown out of the campus as they staged a demonstration over the Nepalese girl student's death.

Nepal Prime Minister KP Sharma Oli had expressed concern over the manner in which the Nepalese students were treated by the KIIT authorities.

Later, the institute tendered an apology and urged the students to return to campus.



Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi also assured complete safety of the Nepalese students after they returned to the campus in KIIT.

The state government has, meanwhile, set up a helpdesk to facilitate the return of Nepalese students and also launched a dedicated International Student Facilitation Cell to support and assist international students across (Public/Private/Deemed) universities in the state.

In a statement, the varsity expressed gratitude to the central government, the Ministry of External Affairs, the Odisha Government, the Nepalese Government, and the Nepalese Embassy in New Delhi for the return of the students.

The authorities also said that in coordination with law enforcement authorities, KIIT had taken immediate steps to restore normalcy and ensure the safety and well-being of all students.

"With the situation stabilised, KIIT-DU engaged in continuous dialogue with the Nepal Embassy, student representatives, and parents to reassure them about the security and support available at the university. Special grievance redressal mechanisms were put in place to address any concerns and enhance the overall student experience," the statement said.

The varsity said that these efforts saw the return of Nepalese students to the campus with "renewed confidence".

"The university has reaffirmed its commitment to maintaining an inclusive, safe, and academically enriching environment for all its students," it added.

As directed by the NHRC, its team has been undertaking an "on-spot" inquiry into the death of the female student and subsequent harassment of the Nepalese students allegedly by KIIT employees.

The NHRC inquiry team, led by its Registrar (Law) Joginder Singh, has collected evidence from the Odisha Police and interacted with the KIIT authorities, students and other persons concerned linked to the incident.

The commission has asked the team to submit its findings by March 10.

Besides Odisha Police and NHRC, the state government's high-level committee headed by the additional chief secretary of the Home Department is also probing the KIIT incident.

The police have meanwhile arrested 11 people, including one engineering student, on the charge of abetment to suicide.

Tribune

### **1,000 Nepalese students returned to campus amid NHRC probe: KIIT**

The Nepalese students were allegedly evicted from the campus by KIIT employees after they demanded justice for 20-year-old Prakriti Lamsal, who died by suicide in her hostel room on February 16

<https://www.tribuneindia.com/news/india/1000-nepalese-students-returned-to-campus-amid-nhrc-probe-kiit/>

PTI | Bhubaneswar, Updated At : 03:30 AM Mar 09, 2025 IST

An agitator holds a poster during a protest over the death of a Nepali student on the Kalinga Institute of Industrial Technology campus in Bhubaneswar on Wednesday. PTI file

Amid the probe by the National Human Rights Commission and Odisha Police into the alleged suicidal death of a BTech student, KIIT University has claimed that 1,000 of the 1,100 Nepalese students, who left the campus in the wake of the February 16 unrest, have returned to the institute in Bhubaneswar.

The private university made this claim on Friday after Odisha's Higher Education Minister Suryabanshi Suraj informed the Assembly that the state government formed a professor committee to ensure a proper academic environment on the KIIT campus.

"As many as 1,000 Nepalese students out of 1,100 have returned to KIIT-DU to resume their academic pursuits after temporarily leaving the campus in the wake of the February 16 incident. The remaining 100 students are on their way and will be arriving soon," the KIIT said in a statement, adding that the students' return demonstrates the strong ties between the institute and its international student community, particularly from Nepal.

The Nepalese students were allegedly evicted from the campus by KIIT employees after they demanded justice for 20-year-old Prakriti Lamsal, who died by suicide in her hostel room on February 16.

The students allegedly were beaten up, verbally abused and even thrown out of the campus as they staged a demonstration over the Nepalese girl student's death.

Telegraph India

## **Amid probe by NHRC, Odisha police into student's suicide, KIIT University claims 1,000 Nepalese students returned to campus**

'The remaining 100 are on their way and will be arriving soon,' the institute said in a statement

<https://www.telegraphindia.com/india/amid-probe-by-nhrc-odisha-police-into-students-suicide-kiit-university-claims-1000-nepalese-students-returned-to-campus/cid/2087805>

PTI Published 08.03.25, 02:46 PM

Amid the probe by the NHRC and Odisha Police into the alleged suicidal death of a B Tech girl student, KIIT University has claimed that 1,000 of the 1,100 Nepalese students who left the campus in the wake of the February 16 unrest have returned to the institute in Bhubaneswar.

The private university made this claim on Friday after Odisha's Higher Education Minister, Suryabanshi Suraj, informed the Assembly that the state government formed a professor committee to ensure a proper academic environment on the KIIT campus.

"As many as 1,000 Nepalese students out of 1,100 have returned to KIIT-DU to resume their academic pursuits after temporarily leaving the campus in the wake of the February 16 incident. The remaining 100 students are on their way and will be arriving soon," the KIIT said in a statement, adding that the students' return demonstrates the strong ties between the institute and its international student community, particularly from Nepal.

The Nepalese students were allegedly evicted from the campus by KIIT employees after they demanded justice for 20-year-old Prakriti Lamsal, who died by suicide in her hostel room on February 16.

The students allegedly were beaten up, verbally abused and even thrown out of the campus as they staged a demonstration over the Nepalese girl student's death.

Nepal Prime Minister K P Sharma Oli had expressed concern over the manner in which the Nepalese students were treated by the KIIT authorities.

Later, the institute tendered an apology and urged the students to return to campus.

Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi also assured the complete safety of the Nepalese students after they returned to the campus in KIIT.

The state government has, meanwhile, set up a helpdesk to facilitate the return of Nepalese students and also launched a dedicated International Student Facilitation Cell to support and assist international students across (Public/Private/Deemed) universities in the state.

In a statement, the varsity expressed gratitude to the central government, the Ministry of External Affairs, the Odisha Government, the Nepalese Government, and the Nepalese Embassy in New Delhi for the return of the students.

The authorities also said that in coordination with law enforcement authorities, KIIT had taken immediate steps to restore normalcy and ensure the safety and well-being of all students.

"With the situation stabilized, KIIT-DU engaged in continuous dialogue with the Nepal Embassy, student representatives, and parents to reassure them about the security and support available at the university. Special grievance redressal mechanisms were put in place to address any concerns and enhance the overall student experience," the statement said.

The varsity said that these efforts saw the return of Nepalese students to the campus with "renewed confidence".

"The university has reaffirmed its commitment to maintaining an inclusive, safe, and academically enriching environment for all its students," it added.

As directed by the NHRC, its team has been undertaking an "on-spot" inquiry into the death of the female student and subsequent harassment of the Nepalese students allegedly by KIIT employees.

The NHRC inquiry team, led by its Registrar (Law) Joginder Singh, has collected evidence from the Odisha Police and interacted with the KIIT authorities, students and other persons concerned linked to the incident.

The commission has asked the team to submit its findings by March 10.

Besides Odisha Police and NHRC, the state government's high-level committee headed by the additional chief secretary of the Home Department is also probing the KIIT incident.

The police have meanwhile arrested 11 people, including one engineering student, on the charge of abetment to suicide.

Except for the headline, this story has not been edited by The Telegraph Online staff and has been published from a syndicated feed.



The Hans India

### **NHRC team holds meeting with Odisha Police**

<https://www.thehansindia.com/telangana/hyderabad-govt-school-teacher-suspended-over-corporal-punishment-951939>

The Hans India Hans News Service | 8 Mar 2025 10:30 AM IST

**HIGHLIGHTS** Bhubaneswar: An NHRC team, which is probing the death of a 20-year-old Nepalese girl student at KIIT University here, has met senior police officers...

Bhubaneswar: An NHRC team, which is probing the death of a 20-year-old Nepalese girl student at KIIT University here, has met senior police officers of the Bhubaneswar-Cuttack Commissionerate. The National Human Rights Commission (NHRC) team began its inquiry into the incident on Thursday, and would continue the exercise on Friday. During the day, they could meet senior KIIT officials and its founder Achyuta Samanta, the officials said.

“We have met the NHRC team at the State guest-house and gave all pertinent information to them. A liaison officer has been specifically assigned to support and facilitate the ongoing investigation by the rights panel,” Police Commissioner S Dev Datta Singh told reporters here. He, along with Bhubaneswar DCP Jagmohan Meena, met the rights panel representatives on Thursday night. They have offered all cooperation to the NHRC team members and apprised them of the situation, under which the girl allegedly died by suicide, another official said.

The NHRC team members were also informed about violence on the campus after the death of Prakriti Lamsal, a third-year Computer Science student at KIIT, he said The NHRC inquiry team, led by its Registrar (Law) Joginder Singh, spent nearly five hours at the KIIT University campus where Lamsal’s body was recovered on February 16 evening.

The team members interacted with the deceased girl’s friends, her hostel inmates and some officials of the KIIT, who allegedly misbehaved with the Nepalese students.

As directed by the rights panel, the team would also look into alleged attacks on Nepalese students by the staff of the private institute.

Hindustan

## एक हजार नेपाली छात्र वापस कैंपस लौटे, NHRC की जांच के बीच KIIT यूनिवर्सिटी का दावा

<https://www.livehindustan.com/national/kiit-university-claims-amid-nhrc-investigation-one-thousand-nepali-students-returned-to-campus-201741429398617.html>

8 मार्च 2025

नेपाली छात्रा की आत्महत्या के कारण चर्चा में आई केआईआईटी यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि घटनाक्रम के बाद कैंपस छोड़कर गए ज्यादातर छात्र वापस आ गए हैं। बाकी के छात्र भी वापस आ रहे हैं और जल्दी ही आ जाएंगे।

बीटेक की छात्रा की कथित आत्महत्या के मामले के बाद ओडिशा की केआईआईटी यूनिवर्सिटी चर्चा में बनी हुई है। फिलहाल इस केस की जांच नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और ओडिशा पुलिस कर रही है। इसी बीच यूनिवर्सिटी की तरफ से दावा किया गया है कि इस मामले के बाद कैंपस छोड़कर 1100 नेपाली छात्रों में से 1000 से ज्यादा छात्र भुवनेश्वर स्थित कैंपस में वापस आ गए हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से यह दावा तब किया गया जब राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने विधानसभा को बताया कि परिसर में शिक्षा के लिए सही माहौल बना रहे इसके लिए प्रोफेसर की समिति का गठन किया गया है।

इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि 16 फरवरी की घटना के बाद गए अधिकांश छात्र वापस आ गए हैं। अब वह वापस फिर से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करेंगे। बाकी बचे 100 छात्र भी रास्ते में हैं और वह भी जल्दी ही वापस आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि नेपाली छात्रों की वापसी संस्थान और उसके अंतरराष्ट्रीय छात्र समुदाय के साथ मजबूत संबंधों को दर्शाती है।

क्या था मामला?

16 फरवरी को नेपाली छात्रा ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली थी। 20 वर्षीय प्रकृति लामसाल की आत्महत्या के बाद नेपाली छात्रों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कथित तौर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ मारपीट की गई और गालियां देते हुए परिसर से बाहर निकाल दिया गया।

मामले के बढ़ने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। सरकार के हस्तक्षेप के बाद यूनिवर्सिटी ने माफी मांगी और छात्रों से कैंपस में वापस लौटने का आग्रह किया। ओडिसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी नेपाली छात्रों को वापस कैंपस में लौटने का आग्रह किया और उनको सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त किया।

Amar Ujala

**Odisha: KIIT आत्महत्या मामला, एनएचआरसी जांच के बीच 1 हजार नेपाली छात्र कैंपस लौटे**

<https://www.amarujala.com/india-news/odisha-kiit-suicide-case-nepalese-student-returns-to-campus-after-nhrc-investigation-2025-03-08>

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर Published by: नितिन गौतम Updated Sat, 08 Mar 2025 04:05 PM IST

सार

देश

केआईआईटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि '16 फरवरी की घटना के बाद अस्थायी रूप से कैंपस छोड़ने वाले 1100 में से 1 हजार नेपाली छात्र अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए लौट आए हैं।'

विस्तार

भुवनेश्वर के केआईआईटी विश्वविद्यालय में बीटेक छात्रा की आत्महत्या मामले की जांच एनएचआरसी और ओडिशा पुलिस द्वारा की जा रही है। अब जांच के बीच 1 हजार नेपाली छात्र वापस कैंपस लौट आए हैं। उल्लेखनीय है कि भुवनेश्वर स्थित विश्वविद्यालय में छात्रा की मौत को लेकर 16 फरवरी को हुई अशांति के मद्देनजर 1100 नेपाली छात्र परिसर छोड़कर चले गए थे। संस्थान के प्रबंधन ने बयान जारी कर बताया है कि इनमें से ज्यादातर छात्र वापस लौट आए हैं।

विश्वविद्यालय ने बयान जारी कर दी जानकारी

विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। इससे पहले ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि केआईआईटी कैंपस में बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन किया गया है। केआईआईटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि '16 फरवरी की घटना के बाद अस्थायी रूप से कैंपस छोड़ने वाले 1100 में से 1 हजार नेपाली छात्र अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए लौट आए हैं। बाकी बचे 100 छात्र रास्ते में हैं और वे जल्दी ही पहुंच जाएंगे।'

क्या है पूरा विवाद

नेपाल की 20 वर्षीय छात्रा प्रकृति लामसाल ने 16 फरवरी को छात्रावास के के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में नेपाली छात्र न्याय की मांग कर रहे थे लेकिन कथित तौर पर केआईआईटी कर्मचारियों ने इन छात्रों को कैंपस से बाहर निकाल दिया था। आरोप है कि प्रदर्शन करने वाले नेपाली छात्रों की पिटाई की गई। साथ ही उनके साथ गाली-गलौज भी की गई और आखिर में उन्हें परिसर से बाहर निकाल दिया गया। इस मुद्दे पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उनके देश के छात्रों के साथ हुए बर्ताव पर चिंता जताई थी।

बाद में इस मुद्दे पर संस्थान ने माफ़ी मांग ली थी और छात्रों से वापस कैंपस लौटने का आग्रह किया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी नेपाली छात्रों को केआईआईटी लौटने पर पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया था।

राज्य सरकार ने नेपाली छात्रों के लिए बनाई हेल्प डेस्क

इस बीच राज्य सरकार ने नेपाली छात्रों की सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए एक एक हेल्प डेस्क भी बनाई है। साथ ही राज्य के सार्वजनिक, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों की सहायता के लिए एक विशेष अंतरराष्ट्रीय छात्र सुविधा प्रकोष्ठ भी शुरू किया है। केआईआईटी ने छात्रों की वापसी के लिए केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय, ओडिशा सरकार, नेपाली सरकार और नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास का आभार जताया है। एनएचआरसी छात्रा की मौत के मामले की जांच कर रही है। जांच टीम का नेतृत्व एनएचआरसी के रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह कर रहे हैं। उन्होंने ओडिशा पुलिस से सबूत एकत्र किए हैं और केआईआईटी अधिकारियों, छात्रों और घटना से जुड़े अन्य संबंधित लोगों से बात की है। जांच टीम को 10 मार्च तक अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

ओडिशा पुलिस और एनएचआरसी के अलावा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति भी इस घटना की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक इंजीनियरिंग छात्र सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।



The Print Hindi

## एनएचआरसी जांच के बीच 1,000 नेपाली छात्र केआईआईटी विश्वविद्यालय लौटे

<https://hindi.theprint.in/india/1000-nepali-students-return-to-kiit-university-amid-nhrc-probe/794315/>

भाषा | 8 March, 2025 05:18 pm IST

भुवनेश्वर, आठ मार्च (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और ओडिशा पुलिस द्वारा केआईआईटी परिसर में एक नेपाली छात्रा की कथित आत्महत्या की जांच के बीच, विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि 16 फरवरी को हुए विरोध के बाद परिसर छोड़ने वाले 1,100 में से 1,000 नेपाली छात्र वापस आ गए हैं।

निजी विश्वविद्यालय ने छात्रों की वापसी का यह दावा शुक्रवार को तब किया जब इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब दिया। ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय में उचित शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए एक समिति का गठन किया है।

केआईआईटी ने एक बयान में कहा, 'कुल 1,100 में से एक हजार नेपाली छात्र अपने अकादमिक कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए लौट आए हैं, जबकि शेष 100 भी जल्द ही वापस आ जाएंगे।'

विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि छात्रों की वापसी इस संस्थान और इसके अंतरराष्ट्रीय छात्रों, खासतौर से नेपाल से आए छात्रों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है।

विश्वविद्यालय के छात्रावास के कमरे में नेपाली छात्रा प्रकृति लाम्साल (20 वर्ष) की 16 फरवरी को कथित आत्महत्या के बाद अन्य नेपाली छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान केआईआईटी कर्मचारियों ने कथित तौर पर नेपाली छात्रों को जबरन परिसर से बाहर किया और अभद्र भाषा का प्रयोग कर उनके साथ मारपीट भी की।

इस घटना को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने भी चिंता व्यक्त की थी। बाद में, विश्वविद्यालय ने माफी मांगते हुए छात्रों से परिसर में लौटने का अनुरोध किया था।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने परिसर में लौटे नेपाली छात्रों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने छात्रों की वापसी के लिए हेल्पडेस्क बनाया और अंतरराष्ट्रीय छात्र सुविधा प्रकोष्ठ शुरू किया जिससे सभी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों की सहायता हो सके।

एक बयान में विश्वविद्यालय ने छात्रों की वापसी के लिए केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय, ओडिशा सरकार, नेपाल सरकार और नयी दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के प्रति आभार व्यक्त किया।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समन्वय में केआईआईटी ने सामान्य स्थिति बहाल करने तथा सभी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं।

विश्वविद्यालय ने कहा कि इन प्रयासों से नेपाली छात्र 'नए विश्वास' के साथ परिसर में वापस लौटे हैं।

इसमें कहा गया है, 'विश्वविद्यालय ने अपने सभी छात्रों के लिए समावेशी, सुरक्षित और शैक्षणिक रूप से समृद्ध वातावरण बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।'

एनएचआरसी के निर्देशानुसार, उनकी टीम छात्रा की मौत और केआईआईटी कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर नेपाली छात्रों को परेशान करने की घटना की जांच कर रही है।

आयोग ने टीम को 10 मार्च तक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

ओडिशा पुलिस और एनएचआरसी के अलावा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति भी केआईआईटी की घटना की जांच कर रही है।

इस बीच पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक इंजीनियरिंग छात्र सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

भाषा

राखी पवनेश

पवनेश

यह खबर 'भाषा' न्यूज़ एजेंसी से 'ऑटो-फीड' द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

Tirhut Now

**जमानत मिलने के बाद भी चौबीस हजार से ज्यादा कैदी जेल से बाहर नहीं निकल सके।**

<https://tirhutnow.com/even-after-getting-bail-more-than-twenty-four-thousand-prisoners-could-not-get-out-of-the-jail/>

Posted by: tirhutnow | March 8, 2025

मुजफ्फरपुर :- देश के विभिन्न जेलों में 24,000 से ज्यादा ऐसे कैदी मौजूद हैं, जो जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद हैं। इसका खुलासा इंडिया जस्टिस और नालसा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार कुल कैदी 24,879 (चौबीस हजार आठ सौ उनासी) हैं, इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार से हैं। बहरहाल मामले को लेकर मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दाखिल किये हैं।

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने बताया कि जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद रहना मानवाधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने पूर्व में ही इस बात को अभिकथित किया था कि जमानत शर्तें पूरी न करने के बावजूद ऐसे बंदियों को रिहा किया जा सकता है, जिन्होंने कुल सजा का एक तिहाई समय जेल में काटा हो। इसके लिए निचली कोर्ट जाना होगा। यह आदेश दुष्कर्म और हत्या जैसी अपराधों में नहीं लागू होता। जमानत के बावजूद जेल में बंद होने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा – 479 के तहत भी इसे लेकर प्रावधान किए गए हैं, हालांकि जानकारी न होने से यह प्रभावी नहीं है। मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने आयोग से अविलम्ब हस्तक्षेप की माँग की है और उच्चस्तरीय जाँच कर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस मामले का खुलासा होने के बाद पूरे देश में हलचल मच गयी है।

Dainik Bhaskar

**जमानत के बावजूद जेल में बंद हैं 24 हजार कैदी:सिर्फ UP, MP और बिहार के 50%, अधिवक्ता इसके झा ने राष्ट्रीय-राज्य मानवाधिकार आयोग में दायर की याचिका**

<https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/24-thousand-prisoners-are-still-in-jail-despite-bail-in-nation-advocate-sk-jha-filed-petition-in-human-right-commission-134608570.html>

जमानत के बावजूद जेल में बंद हैं 24 हजार कैदी:सिर्फ UP, MP और बिहार के 50%, अधिवक्ता इसके झा ने राष्ट्रीय-राज्य मानवाधिकार आयोग में दायर की याचिका

देश की जेलों में एक चिंताजनक स्थिति सामने आई है। इंडिया जस्टिस और नालसा की सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट के अनुसार, 24,879 कैदी ऐसे हैं जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत राशि जमा न भर पाने के कारण वो अभी भी जेल में बंद हैं। इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक कैदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के हैं। अकेले बिहार में 3,345 ऐसे कैदी हैं, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन वो अभी भी जेल में हैं।

मानवाधिकार अधिवक्ता इसके झा ने इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में अलग-अलग याचिकाएं दायर की है। उन्होंने बताया कि यह मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जानकारी के अभाव में भी जेल में बंद हैं कैदी

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि जो कैदी अपनी तीन-तिहाई सजा काट चुके हैं, उन्हें बिना शर्त जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि यह छूट दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में नहीं दी गई थी। अधिवक्ता झा के अनुसार, कई कैदी जानकारी के अभाव में भी जेल में बंद हैं। इसलिए मानवाधिकार आयोग से इन कैदियों की रिहाई के लिए हस्तक्षेप करने की सिफारिश की गई है।